+91 8434931877,
+91 7250667974

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

A Serious & Genuine Institute For UPSC & BPSC

PATNA

DAILY CURRENT AFFAIRS

For

UPSC/BPSC

DATE

29.06.2024

ENGLISH

Collect **FREE** copy of Monthly Current Afairs Magazine From our Centre

achieversiaspatna@gmail.com

www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opp. A.N. College) Patna-800001

दिल्ली एयरपोर्ट पर छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत

- दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।
- टर्मिनल 1 के लिए निर्धारित सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले की गहन जांच करने के लिए एक टीम को नियुक्त किया है।
- पुलिस ने आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया है।
- दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) GMR समूह, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फ्राफोर्ट एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज के नेतृत्व में एक संयुक्त उद्यम है

सोरेन को जमानत मिली: HC ने कहा 'आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं'

- झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दे दी।
- न्यायालय के आदेश में न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय ने कहा, "यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है।" यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शर्त को पूरा करता है।
- श्री सोरेन की रिहाई का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में इस नवंबर में चुनाव होने हैं।
- मई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 6.3% रह गई

भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट की 'गहरी पक्षपातपूर्ण' आलोचना की

- भारत ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह "गहरी पक्षपातपूर्ण" है और "मुद्दों का एकतरफा प्रक्षेपण" दर्शाती है।
- साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट में "कुछ" कानूनी निर्णयों पर सवाल उठाए गए हैं।
- "यह अभ्यास अपने आप में आरोप-प्रत्यारोप, दयनीय प्रस्तुति, तथ्यों का चयनात्मक उपयोग, पक्षपाती स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दे का एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण है। यह भारत में कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के चित्रण तक फैला हुआ है। इसने पहले से ही चुनिंदा घटनाओं को चुना है, साथ ही एक पूर्वकल्पित कथा भी है," श्री जायसवाल ने कहा।
- धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी गृह विभाग की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को समर्पित 69 पृष्ठ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। साथ ही लोग धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

FATF मूल्यांकन में भारत ने 'उत्कृष्ट परिणाम' हासिल किया

- भारत ने 2023-24 के दौरान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। सिंगापुर में 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित FATF के पूर्ण अधिवेशन में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया गया है, जिसने भारत को "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी की सूची में रखा है। यह अंतर केवल चार अन्य G20 देशों द्वारा साझा किया गया है।
- FATF के बयान में कहा गया है कि भारत अपनी आवश्यकता के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- । देश की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और प्रोफिल्ट्रेशन फाइनेंसिंग व्यवस्था अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुंच और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना शामिल था।
- एफएटीएफ अवैध धन, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन आदि का मुकाबला करने के लिए काम करता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सभी गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह की जांच के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होना चाहिए।

- भारत, लंदन और अफ्रीका के शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं की गर्भावस्था का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (OGTT) की जगह HbA1C टेस्ट किया जाना चाहिए।
- HbA1C टेस्ट का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ केयर में भी किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 90% से अधिक गर्भावधि मधुमेह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होता है।
- OGTT एक केंद्रित 75 ग्राम मौखिक घोल है जिसे उपवास के समय लिया जाता है और फिर दो से तीन घंटे प्रतीक्षा की जाती है और फिर परीक्षण किया जाता है।
- Hb1Ac परीक्षण किट रक्त की एक बूंद से गर्भावस्था की जांच करती है। इसका उपयोग पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण किट के रूप में किया जा सकता है, जहां घर पर भी परीक्षण किया जा सकता है।

- **सरकार पर पूरा भरोसा, एनडीए की सौ दिन की योजना में मणिपुर भी शामिल मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह** ने कहा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर पर सकारात्मक चर्चा शुरू कर दी है और यह एक बड़ी उपलब्धि है कि संकट का समाधान नवगठित एनडीए सरकार की 100 दिन की योजना का हिस्सा है।

- बीरेन सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि केंद्र मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली मांग के आगे नहीं झुकेगा। हाल ही में कुकी जो समूह ने अलग राज्य की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि मौजूदा संघर्ष को खत्म करने का यही एकमात्र समाधान है।

- .. 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी
- ।अमरनाथ यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई, दिल्ली के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से 4603 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की होगी। पहलगाम और सोनमर्ग से अमरनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है।

विश्व

बाइडेन, ट्रंप में राष्ट्रपति पद की बहस में भिड़ंत

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप पहली लाइव राष्ट्रपति पद की बहस में आमने-सामने हुए।
- दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए, निजी आरोप लगाए।
- डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर अर्थव्यवस्था में विफलता, यूक्रेन पर युद्ध, विश्व मंच पर विफलता, सीमा और आव्रजन मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाया।
- श्री जो बाइडेन ने ट्रंप पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाने का आरोप लगाया।

रूस ने काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ 'प्रतिक्रिया' की चेतावनी दी।

- रूस के रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन उड़ानों के लिए "प्रतिक्रिया" तैयार करने का आदेश दिया।
- रूसी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन की "बढ़ी हुई तीव्रता" का उल्लेख किया। कहा कि वे "खुफिया जानकारी" संचालित करते हैं।
- "यह कीव शासन के पक्ष में यूक्रेन में संघर्ष में अमेरिका और अन्य नाटो देशों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।"
- मंत्रालय ने कहा, "नाटो सदस्य इसके लिए जिम्मेदार होंगे।"

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने संघीय एजेंसियों की शक्ति पर अंकुश लगाया

- शुक्रवार को एक बड़े फैसले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुरानी कानूनी मिसाल को खारिज कर दिया, जिसमें वायु गुणवत्ता से लेकर दवा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिकियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को विनियमित करने की संघीय एजेंसियों की शक्ति पर अंकुश लगाया गया।
- 6-3 वोट से, न्यायाधीशों ने शेवरॉन बनाम नेचुरल डिफेंस काउंसिल के 1984 के ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर भाषा अस्पष्ट है तो न्यायाधीशों को कानून की "उचित" व्याख्या निर्धारित करने में सरकारी विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए।
- यह फैसला न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में निर्णय देने और आदेश पारित करने के लिए अधिक शक्ति देगा। न्यायाधीशों को अब अधिक बार सरकारी विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विश्व शासन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाएं: शी

- "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों" की 70वीं वर्षगांठ पर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक दक्षिण से वैश्विक शासन को सुधारने और विकसित करने और इसे अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।
- उन्होंने कहा कि चीन का रास्ता शांतिपूर्ण विकास का है, न कि आधिपत्य और लूट का, उन्होंने यह बात पश्चिम पर परोक्ष हमला करते हुए कही। श्री शी ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की प्रशंसा की। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत चीनी विदेश नीति की पहल थी जिसका उल्लेख पहली बार 1954 में भारत-चीन संबंधों में किया गया था। ये पांच सिद्धांत हैं: परस्पर सम्मान, परस्पर अहिंसा, आंतरिक मामलों में परस्पर अहस्तक्षेप, समानता और सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। बाद में चीन ने म्यांमार के साथ संबंधों में इसका इस्तेमाल किया। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन का सिद्धांत था

संपादकीय

एक नई शुरुआत

- जीएसटी परिषद को व्यापक सुधार की दृष्टि से नहीं चूकना चाहिए
- जीएसटी परिषद की बैठक पिछले सप्ताह नौ महीने में पहली बार हुई थी।
- इसमें लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों में 20,000 रुपये तक के छात्रावास आवास और रेलवे सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखना शामिल है।
- सभी जीएसटी पंजीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।
- जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाना चर्चा के प्रमुख मुद्दों में से एक है।

कर्ज का जाल

- केन्या को अपने लोगों को दंडित किए बिना अपने कर्ज की सेवा करने के तरीके खोजने चाहिए
- संपादकीय केन्या में करों में वृद्धि के सरकार के फैसले पर हाल ही में हुई हिंसा के बारे में है।
- केन्या आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकार ने आईएमएफ से लगभग 1 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया है। आईएमएफ की शर्तों में से एक करों में वृद्धि करना था।
- इसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई लोग विधानसभा भवन में घुस गए जिसके कारण पुलिस ने गोलीबारी की और लगभग 23 लोगों की मौत हो गई।
- राष्ट्रपति रुटो ने अब कर वृद्धि के निर्णय को रद्द कर दिया है।
- संपादकीय में कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय और द्विपक्षीय ऋणदाताओं को कर वृद्धि जैसे अतिरिक्त बोझ डाले बिना ऋणग्रस्त देशों को किसी भी ऋण जाल से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए।